झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

|| संकल्प ||

विषय:- केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत नागरिकों की सहायता के लिए निकटतम सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों को खोजने के लिए शौचालयों का गूगल मैपिंग करने हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत योजना हित में Quality Council of India (QCI) से मनोनयन के आधार पर सेवा लेने के सम्बन्ध में।

6324
06/10/17

74 वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। अतः नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी शहरी नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है।

2. नगर निकाय सामुदायिक शौचालयों और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के उपरांत उनके रखरखाव, वास्तविक उपयोग, कार्यक्षमता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस हेतु एक प्रणाली की आवश्यकता है, ताकि नगर निकाय नागरिकों को सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों की खोज में मदद कर सके।
3. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नागरिकों को निकटतम सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों की खोज में मदद करने के लिए आई० सी० टी० के प्रभाव पर विचार किया गया है और तदनुसार Google Maps के साथ भागीदारी की गयी है, जिससे सभी नागरिकों को सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय का पता लगाने में सुविधा देगी।
4. स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 में नगर निकायों का मूल्यांकन Google मानचित्र पर सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों के डेटा की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
5. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शौचालयों का गूगल मैपिंग Quality Council of India (QCI) से कराये जाने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है | Quality Council of India (QCI) नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक गैर-लाभकारी स्वायत्त संस्था है।
6. भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देश के अनुसार राज्य के 41 नगर निकायों में शौचालयों का गूगल मैपिंग, आई० सी० टी० प्लेटफार्म एवं हेल्पडेस्क का कार्य Quality Council of India (QCI) द्वारा कुल 11.23 लाख रुपये में किया जाएगा, जिसमे सभी व्यय शामिल हैं (लागूकरों के अतिरिक्त) । Quality Council of India (QCI) की टीम प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम प्रबंधन के लिए संबंधित शहरी निकायों का दौरा करेगी । टीम 3-5 दिनों के लिए निकायों में रहकर निकाय के कर्मचारियों को Handholding सहायता प्रदान करेगी एवं डेटा

एकत्र करेगी। QCI द्वारा दो माह के अन्दर मैपिंग का कार्य किया जाएगा। इस पर होने वाले व्यय का भुगतान स्वच्छ भारत मिशन के Capacity Building मद से किया जाएगा।

7. वर्णित परिपेक्ष्य में केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत नागरिकों की सहायता के लिए निकटतम सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों को खोजने के लिए शौचालयों का गूगल मैपिंग करने हेतु कंडिका-6 में उल्लेखित शर्तो के अनुसार झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत योजना हित में मनोनयन के आधार पर सेवा लेने हेतु Quality Council of India (QCI) को एजेंसी के रूप मे नियुक्त किया जाता है।
8. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 19.09.2017 को मद संख्या – 03 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्य के राज्यपाल के आदेश से,

6.10.17

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-SUDA/SBM/QCI/37/2017..... 6324 **रांची,दिनांक-.....** 06/10/17

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि मुद्रित संकल्प की एक सौ प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराई जाये।

6.10.17

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-SUDA/SBM/QCI/37/2017..... 6324 **रांची,दिनांक-.....** 06/10/17

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री / प्रधान सचिव के आप्त सचिव/ निदेशक,राज्य शहरी विकास अभिकरण/ निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/ सभी आयुक्त/उपायुक्त/नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/ विशेष पदाधिकारी / Quality Council of India (QCI) / बजट शाखा / नोडल पदाधिकारी e – गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.10.17

सरकार के प्रधान सचिव